



E-ISSN: 2706-9117

P-ISSN: 2706-9109

www.historyjournal.net

IJH 2025; 7(10): 123-127

Received: 25-08-2025

Accepted: 28-09-2025

डॉ. रवीन्द्र कुमारअसिसटेंट प्रोफेसर, इतिहास
दाउदनगर कॉलेज दाउदनगर,
औरंगाबाद, बिहार, भारत

बिहार के अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन में गांधीजी की भूमिका

रवीन्द्र कुमार**DOI:** <https://www.doi.org/10.22271/27069109.2025.v7.i10b.546>

सारांश

भारत की सामाजिक व्यवस्था में सर्वप्रथम चतुर्वर्णीय वर्ण-व्यवस्था की संरचना कर्म आधारित था। इसमें प्रारंभ में सोपानक्रम नहीं था, सभी वर्ण एक की स्तर पर थे। एक ही परिवार में चारों वर्णों के लोग एक साथ निवास करते थे। कलांतर में जन्म आधारित जाति-व्यवस्था के रूप में इसका रूढ़ रूपांतरण हो गया अब सामाजिक संरचना सोपानीकृत हो गया। कर्मकाण्ड के आधार पर जातियाँ पवित्र एवं अपवित्र होने लगा और एक दूसरे से स्पर्श होना भी प्रतिबंधित हो गया इसप्रकार अस्पृश्यता का उदय हुआ। अस्पृश्य जातियों को अब मानवोचित नैसर्गिक अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समय-समय पर इस कुप्रथा के विरुद्ध धार्मिक आधार पर चुनौतियाँ दी जाती रही और आजाद भारत में संवैधानिक कानून बनाकर इसके समूल उन्मूलन का प्रयास किया गया। नई प्रौद्योगिकी के विकास, लोकतांत्रिक शिक्षा के प्रसार, वैश्वीकरण एवं रोजगार के नये अवसरों का विकास जैसे तत्व जातिगत सोपानक्रम के कर्मकांडीय पदस्थिति को बदलने में मदद दी है।

कुटशब्द: वर्ण-व्यवस्था, कर्मकाण्ड, अस्पृश्यता

प्रस्तावना

महाकवि रवीन्द्रनाथ ने पूना में 27 सितम्बर 1932 को कहा था कि—“आज दृढ़ संकल्प लेकर हम सभी महात्माजी के साथ युगों के इस भार से मुक्त होने के महान कार्य में लग पड़े। यह भारत के करोड़ों-करोड़ देशवासियों को केवल जन्म के कारण घोर अपमान का जीवन व्यतीत करने को बाध्य करता रहा है तथा मानवोचित मर्यादा से वंचित करता रहा है, उन्हें वह सहानुभूति नहीं मिलती है जो मानव मात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है।”

महाकवि की यह उक्ति अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा के उन्मूलन के संबंध में कहा गया था। यह एक सामाजिक बुराई है जो एक विशेष जाति को उसके कार्य के पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर किया जाता था। अछूत जातियों का निवास मुख्य गाँव से बाहर असुविधाग्रस्त स्थानों पर होता था। इन्हें पीने का पानी भी सार्वजनिक कुँए से नहीं लेने दिया जाता था एवं इनके लिए मंदिर प्रवेश वर्जित था। छुआछूत की समाप्ति के लिए गाँधीजी ने मूलतः एक धार्मिक दृष्टिकोण अपनाया। प्रायश्चित कृत्य के रूप में सवर्ण हिन्दूओं द्वारा मंदिर प्रवेश कराने के आंदोलन का प्रारंभ और घरेलू नौकर भंगी का महिमामंडन उनके पास इस समस्या का समाधान था। इस अभियान ने अस्पृश्यता के नैतिक एवं धार्मिक आधार को काफी कमजोर किया। लेकिन भिक्खू पारिख का तर्क है कि—“उनका यह प्रयास आर्थिक एवं राजनैतिक मूलों को नष्ट करने में असफल रहा उसने अछूतों के महिमामंडित तो किया लेकिन उनको कोई शक्ति प्रदान नहीं कर सका”¹।

महात्मा गाँधी बचपन से छुआछूत जैसी प्रथा के विरोधी थे, बचपन में अपनी माँ के मना करने के बाद भी वे “उक्का” जो उनके घर में शौचालय की सफाई करता था के साथ सम्पर्क में आने से नहीं हिचकते थे। उनकी माँ सम्पर्क के बाद उन्हें स्नान करने को कहती थी इसपर गाँधी का तर्क था कि जब वह हमें गंदगी साफ कर सेवा करता है तो वह हमें कैसे दूषित कर सकता है³।

1893 से 1914 तक अफ्रीका प्रवास के दौरान उन्हें विभिन्न स्थानों पर नस्लभेदी अपमान सहना पड़ा। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय मोरित्सवर्ग स्टेशन पर उन्हें नस्ली आधार पर ट्रेन से उतार दिया गया⁴। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली कहते थे और जहाँ निवास करते थे उसे “कुली लोकेशन” कहते थे। कुली लोकेशन भारत की ‘भंगी-वस्ती’ ‘ढेडवाडा’ या यूरोपीय यहूदी बस्ती ‘घेटो’ के समान था। जहाँ जीवन निर्वाह के मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था। नस्ली भेदभाव के विरोध में कानूनी लड़ाई एवं सत्याग्रह के प्रयोग प्रथम बार अफ्रीका में किया⁵।

Corresponding Author:**डॉ. रवीन्द्र कुमार**असिसटेंट प्रोफेसर, इतिहास
दाउदनगर कॉलेज दाउदनगर,
औरंगाबाद, बिहार, भारत

पुनः 1915 में भारत वापसी के बाद यहाँ के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया। एक तरफ उपनिवेशी शासन के विरुद्ध भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, तिलक एवं एनी बेसेन्ट के नेतृत्व में होमरूल आंदोलन अपने चरम पर था वहीं दूसरी ओर बंगाल विभाजन, सूरत फूट और साम्प्रदायिकता के आधार पर 1909 में मॉर्ले-मिण्टो रिफॉर्म द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना 1932 में साम्प्रदायिक पंचाट द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर कर रहा था।

इसके विरुद्ध महात्मा गाँधी ने साम्प्रदायिक एकता एवं भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत उन्मूलन पर जोर दिया। कांग्रेस भी पहले छुआछूत आंदोलन के प्रति उतना गंभीर नहीं था लेकिन गाँधीजी ने अपने सभी आंदोलनों में अस्पृश्यता उन्मूलन को सम्मिलित किया एवं इसको व्यापक नैतिक आधार भी प्रदान किया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में छुआछूत समाप्ति को स्वराज प्राप्ति के बुनियादी शर्त घोषित किया ⁶।

महात्मा गाँधी के समक्ष छुआछूत से संबंधित एक घटना उनके साबरमती आश्रम में घटी जहाँ एक वैष्णव अंत्यज दूदाभाई के आश्रम में रहने पर उनको विरोध का सामना करना पड़ा। उनके आश्रम का खर्चा कट्टर समझे जाने वाले हिन्दूओं से मिलता था जो अब बंद हो गया और बहिष्कार की खबर फैल गई। ऐसी परिस्थिति में गाँधीजी अपने साथियों के समक्ष एक विचार रखा—“यदि हमारा बहिष्कार हो और हमें कहीं से मदद न मिले तब भी अब हम अहमदाबाद नहीं छोड़ेंगे। भंगी टोले में जाकर उन्हीं के साथ रहेंगे और जो कुछ मिलेगा उसपर या मजदूरी करके गुजारा करेंगे।” यह घटना छुआछूत के प्रति उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं ⁷।

एतिहासिक पक्ष

लगभग 1500 से 1000 ई.पू. वैदिक काल में चतुर्वर्णीय विभाजन भारत की सबसे प्राचीन सामाजिक विभाजन था जिसमें चार वर्ण के रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की उत्पत्ति हुई। यह वर्ण विभाजन कर्म सिद्धांत पर आधारित था और उसमें समानता की स्थिति थी कोई सोपानीकृत कर्मकांडीय स्थिति नहीं थी। उस काल में एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग वर्णों के कार्य करते हुए एक साथ निवास करते थे। बाद के काल में यह विभाजन जन्म आधारित होने लगा और कर्मकांडीय प्रधानता बढ़ने लगी ⁸। कुछ स्मृति में अस्पृश्य जातियों की संख्या सात बताई गयी है जिसमें रजक, चर्मकार, नट, वरुड, कैवर्त्य, धीवर, भेद तथा भील थे वहीं व्यास स्मृति में कोली, पुस्कर और वराट भी शामिल थे। बृहधर्म एवं स्कंद पुराण में इसकी संख्या अठारह थी। ब्रह्मपुराण के अनुसार बौद्ध, जैन, पाशुपत, लोकायन एवं कापालिकों को स्पर्श करने से व्यक्ति को सवस्त्र स्नान करके शुद्ध होना पड़ता था।

छुआछूत से संबंधित जानकारी भारतीय इतिहास के स्रोत में मिलते हैं मेगास्थनीज, स्ट्रबो एवं डायोडोरस के अनुसार भारत में दास नहीं थे एवं इस प्रकार के कुरीति का वर्णन नहीं करता वहीं फाहियान और अलबेरुनी की रचनाओं में इसका व्यापक वर्णन है ¹²। समय समय पर इन व्यवस्थाओं को अंदर से चुनौती मिलता रहा है जैसे मध्यकाल में भक्ति आंदोलन से मिला जिसने धार्मिक और सामाजिक जीवन के कर्मकांडीय बुनियाद को चुनौती देकर भक्ति पर बल दिया ¹³।

यह वर्ण विभाजन वस्तुतः बाद की सामाजिक वास्तविकता के लिए कुछ विशेष प्रासंगिक नहीं रहा जिसमें सभी क्षेत्रों के सामाजिक श्रेणी की अवधारणा बनायी जा सके। एक विकसित प्रथा के रूप में छुआछूत का विकास तीसरी से छठी सदी के बीच हुआ जब अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप नई जातियों का अभ्युदय हुआ। जन्म के आधार पर कुछ नई जातियाँ

इन चार वर्ण के अंतर्गत नहीं आ रही थी तो इन्हें ‘पंचम’ के नाम से अलग श्रेणी में रखा गया और इन्हें अतिशुद्ध कहा जाने लगा⁹। इनकी स्थिति कर्मकांडीय पदसोपान में सबसे नीचे रखा गया और इसे सामाजिक अधिकारों से वंचित किया जाने लगा। इसके अलावे एक समाज का दूसरे समाज से युद्ध आदि के कारण समिश्रण भी शुरू हो गया था जिसके कारण अलग-अलग सामाजिक खण्ड निर्मित होने लगे थे और उनके बीच दूरी बढ़ने लगा था।

उपनिवेश कालीन एवं वर्तमान पक्ष

भारत में सामाजिक संगठन की वास्तविक इकाई जाति व्यवस्था है। ‘कास्ट’ पुर्तगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सामाजिक खण्ड होता है कास्ट को ही भारतीय समाज में जाति शब्द से सम्बोधित किया जाता है। जाति की उत्पत्ति वर्ण से मानी जाती है लेकिन वर्ण व्यवस्था जहाँ कर्म आधारित था वहीं जाति-व्यवस्था जन्म आधारित रहा। पारंपरिक भारतीय समाज में जाति-व्यवस्था विभिन्न समूहों एवं व्यक्ति के बीच सभी प्रकार के संबंधों का आधार रहा है। जातीय व्यवस्था का केन्द्रीय आधार पवित्र एवं अपवित्र की संकल्पना पर आधारित पदसोपानकर्म है जिसमें विभिन्न जातियों को उसके वंशानुगत पेशा के पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर उच्च एवं निम्न कर्मकांडीय स्थिति प्राप्त होती है। लुई ड्यूमा के अनुसार—“पवित्र एवं अपवित्र की संकल्पना जाति व्यवस्था की केन्द्रीय संकल्पना है जो द्विध्रुवीय विरोध पर आधारित है। भारतीय समाज में पारलौकिकता लौकिकता को अपने अंदर समेट लेता है जो ब्राह्मण को क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र से शक्तिशाली बनाता है ¹⁰।”

सामाजिक इतिहासकारों का तर्क है कि कर्मकांडीय श्रेणीपद शक्ति संरचना से कभी असंबद्ध नहीं रही। राजा की स्थिति कभी उतना खोखला नहीं रहा जितना कुछ उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने दिखाया है। इस स्थिति में पेशे की प्रकृति और शक्ति केन्द्र से दूरी जैसे तत्व किसी जाति के कर्मकांडीय श्रेणी पदस्थिति का निर्धारण करते हैं अर्थात् शक्ति, संपदा एवं श्रेणी में गहरा संबंध रहा है और इसी आधार पर उच्च एवं निम्न जाति का विभेदीकरण किया गया ¹¹। श्री निवास जैसे मानवशास्त्री ने प्रभु जाति की संकल्पना से जाति व्यवस्था के कर्मकांडीय व्यवस्था में परिवर्तन को दिखाया है।

जजमानी प्रणाली हिन्दू जातीय प्रणाली का सामाजिक-आर्थिक आधार रहा है और भारत में कृषक सामाजिक संरचना का हिस्सा है। जजमानी प्रणाली के अंतर्गत हरेक जातीय समूह को अन्य जाति के परिवारों को कुछ मानकीकृत सेवाएं देनी होती हैं। भूमिहीन अछूत जाति के लोग सेवक जातियों से आते हैं जबकि भू-स्वामी उँची जातियों के जिन्हें जजमान या संरक्षक कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले ये सेवा आधारित संबंध जजमानी व्यवस्था कहलाता है। (विलियम वाइजर—द हिन्दू जजमानी सिस्टम 1936)

उपनिवेशी शासन ने अपने संस्थाओं और नीतियों को नए सिरे से निरूपण करके उसे नई शक्ति एवं जीवन दान दिया। जमीन अब बाजारी माल बन गई, नए कानून के सामने समानता, न्याय-प्रशासन एक सुस्थापित सिद्धांत बन गया। शिक्षा संस्थान और सार्वजनिक रोजगार को जाति या पंथ से हटाकर प्रतिभा के लिए मुक्त कर दिया गया। प्राच्यवादी विद्वानों ने जाति-प्रथा को हिन्दू सामाजिक संगठन का सबसे अनिवार्य तत्व पाया। हारबर्ट रिज्जले ने जाति की धारणा को एक नस्ली आयाम प्रदान किया। 1901 के जनगणना कमिश्नर रिज्जले ने सभी जातियों को गिनती के साथ-साथ सोपानकर्म में उसकी स्थिति निर्धारित कर उसे दर्ज करने का प्रस्ताव पास किया। यह व्यवस्था भारतीय जनता को जातिगत सोपानकर्म को रूढ़ बनाने का सरकारी प्रयास था। डर्क्स ने इसे भारतीय समाज का उपनिवेशी रूप कहा। तदुपरांत जनगणना केन्द्रित जातिगत आंदोलन में लोग संलग्न होने लगे

और उच्चि कर्मकांडी श्रेणीक्रम पाने के लिए जनगणना कमिशनर को आवेदन देने लगे। ये उर्ध्वमुखी गतिशील समूह 'संस्कृतिकरण' की प्रक्रिया द्वारा अपनी नई स्थिति को वैध बनाने का प्रयास किया ¹⁴।

पश्चिमीकरण के फलस्वरूप एक जाति के सदस्यों के बीच क्षैतिज एकजुटता बढ़ी और उन्होंने अनेक जातीय संगठन बनाए। ये जाति संगठन जाति प्रथा की स्थितियों में फेरबदल न करके सामाजिक संगठन के आधार को ही चुनौती दे दी। पश्चिम और दक्षिण भारत के गैर-ब्रह्मण आंदोलन इसके उदाहरण हैं। 1873 में ज्योति बा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। फूले का तर्क था कि-शूद्र एवं अतिशूद्र जातियों की बदहाली का कारण ब्रह्मणों का प्रभुत्व और शक्ति एवं अवसरों पर उनका एकाधिकार था। महाराष्ट्र के गैर-ब्रह्मण आंदोलन ने दो समानांतर प्रवृत्तियों का विकास किया-एक अधिक धनी गैर-ब्रह्मण के नेतृत्ववाली रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग जो अपनी मुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार से आस्था रखते थे। दूसरा इस आंदोलन ने एक अतिवादी प्रवृत्ति का विकास किया जिसका प्रतिनिधित्व सत्यशोधक समाज करता था; उसने बहुजन समाज और सेठजी भटजी के बीच सामाजिक विभाजन को वाणी देकर एक वर्गीय अंतः तत्त्व का विकास किया ¹⁵।

पश्चिमी भारत में गैर-ब्रह्मण आंदोलन का पहचान यदि कुनबी और मराठा से था तो मद्रास प्रसीडेंसी में उसका संबंध वेल्लालो और द्रवीड. से था। 1916 में सी. एन. मुदालियार के नेतृत्व में एक गैर-ब्रह्मण घोषणपत्र के प्रकाशन एवं गैर-ब्रह्मणों की एक औपचारिक पार्टी के रूप में "जस्टिस पार्टी" का गठन हुआ। इसने काँग्रेस का विरोध एक ब्रह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया और गैर-ब्रह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जो मार्ले-मिटो सुधार में मुसलमानों को दिया गया था। उपनिवेशी नौकरशाही से समर्थन पानेवाली इस मॉग को 1919 के मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में मद्रास की विधायिका में गैर-ब्रह्मणों के लिए अठाइस सीटें सुरक्षित कर दी गई ¹⁶।

1920 में कोल्हापुर के महाराजा की अध्यक्षता में नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित परिषद् इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। 1926 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया गया जिसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष एम सी राजा थे। डॉ. अंबेडकर इस सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए लेकिन इसके उपाध्यक्षों में एक उपाध्यक्ष चुने गये, बाद में इन्होंने इस संगठन से त्यागपत्र देकर 1930 में नागपुर में एक सम्मेलन कर अखिल भारतीय दलित संघ का गठन किया। दलितों के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अभाव में पर्याप्त प्रतिनिधि पाने के लिए डॉ. अंबेडकर अलग निर्वाचक मंडल की मॉग सबसे पहले साइमन कमीशन से की और गोलमेज सम्मेलन में भी अपनी रूख पर कायम रहे। इस निर्वाचक मंडल की मॉग का एम. सी. राजा ने विरोध किया। इसी समय हिन्दू महासभा के अध्यक्ष बी. एस. मुंजे एवं एम. सी. राजा के बीच एक समझौता हुआ। इसप्रकार दलित नेतृत्व निर्वाचक मंडल के प्रश्न पर बंटो हुआ था ¹⁷।

16 अगस्त 1932 को रैम्जे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में साम्प्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई। इस कानून के तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मॉग को स्वीकार कर लिया गया। मुसलमान एवं सिक्ख पहले से अल्पसंख्यक माने जाते रहे हैं अब दलित भी अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आ गये। दलित वर्ग का शेष हिन्दू समाज से अलग करने के प्रयास का लगभग सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने विरोध किया ¹⁸।

साम्प्रदायिक निर्णय के समय गाँधीजी यरवदा जेल में थे और वही से इस घोषणा का प्रबल विरोध किया और 20 सितम्बर 1932 से जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने इसे हिन्दूवाद एवं दलित दोनों के लिए खतरा कहा। पृथक निर्वाचन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह अछूतों के लिए हमेशा

अछूत बने रहने की बात सुनिश्चित करता है। उन्हें अलग समुदाय बनाने की जरूरत नहीं बल्कि छुआछूत की कुरीति को जड़. ये उखाड़. फेकने की है। प्रेस को दिए बयान में उन्होंने कहा-"मुझे अपनी जिन्दगी की परवाह नहीं, इस पवित्र उद्देश्य के लिए ऐसी सैकड़ों जिन्दगियाँ कुर्बान हो जाए तो भी उस जुल्म का प्रायश्चित्त नहीं हो सकता जो हिन्दूओं अपने गरीब भाई-बहन पर ढाए हैं ¹⁹।"

अनशन के कारण महात्मा गाँधी का स्वास्थ्य गिरने लगा। मदनमोहन मालवीय, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और राज गोपजाचारी के प्रयास से गाँधी एवं अम्बेडकर के बीच 26 सितम्बर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे 'पूना पैक्ट या पुना समझौता' के नाम से जानते हैं। इस पैक्ट द्वारा दलित निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया लेकिन प्रांतीय विधान मंडल में दलित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया एवं केन्द्रीय विधानमंडल में दलितों संख्या में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया गया। इसके बाद गाँधीजी दो साल तक सारे कामकाज छोड़कर छुआछूत आंदोलन में जुटे रहें। जेल से छुटने के बाद गाँधीजी वर्धा गए जहाँ से 7 नवम्बर 1933 को अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की जो 29 जुलाई 1934 तक अर्थात् नौ महीने तक देश का दौरा करते रहें, इस यात्रा में उन्होंने बीस हजार किलोमीटर की यात्रा तय की। ट्रेन, कार, बैलगाड़ी और जहाँ कुछ नहीं मिला वहाँ पैदल यात्रा की। सामाजिक कार्यकर्ताओं से सब कुछ छोड़कर दलितों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक उत्थान के लिए कार्य करने की अपील की। इस कार्य में दो बार 8 मई एवं 16 अगस्त 1933 को अनशन पर बैठे। इस आंदोलन के दौरान कट्टरपंथियों और सामाजिक प्रतिक्रियावादियों के विरोध का सामना करना पड़ता था। 25 जून 1934 पर पूना में एक कार पर गाँधीजी बैठे हैं समझकर हमला कर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया इस प्रकार के हमले अनेकों जगह पर हुए ²⁰।

संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के लिए अम्बेडकर को चुनकर काँग्रेस ने दलित प्रतिरोध को समाहित करने का प्रयास किया। जैसा कि एल्योनोर जोलियट ने कहा-लगा कि गाँधी-काँग्रेस-अस्पृश्यता की स्थिति की सभी धाराएँ एक साथ आ गई हो।

बिहार में अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन

महात्मा गाँधी राजनीति आंदोलन की शुरुआत बिहार से प्रारंभ की थी उनके द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में बिहार के लोगो ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। गाँधी द्वारा चलाए गए अस्पृश्यता आंदोलन का बिहार में बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। 27 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक देश में अस्पृश्यता सप्ताह मनाया गया। 30 सितम्बर को अस्पृश्यता विराधी लीग की स्थापना दिल्ली में किया गया और सभी प्रांतों में इसकी शाखाएँ खोली गई। बिहार में हरिजन उत्थान का काम पहले शुरू हो गया था। 17 जुलाई 1932 को गया के मॉडल स्कूल में एक सभा आयोजित की गई जिसमें एक मेहतर ने सभा में भाषण दिया एवं उपस्थित लोगो के बीच इलाइची एवं सुपारी वितरित किया जिसे अनेक लोगो ने सहर्ष ग्रहण किया। गया, नवादा एवं औरंगाबाद में कई सभाएँ हुई जिसमें सवर्ण हिन्दू एवं हरिजन सम्मिलित हुए। अनेक स्थानों पर एक दूसरे को गले लगाते थे। 1932 के मध्य शाहाबाद, आरा, बक्सर, भभुआ एवं दूर्गावती में ऐसी सभाएँ हुई। पटना जिले में इस प्रकार की सभाएँ-पटना सीटी, बाढ़, मोकामा, बख्तियारपुर, बिहारशरीफ, दानापुर, विहटा, मनेर, खगौल और विक्रम में हुई। हरिजनो के लिए कई स्थानों पर मंदिर प्रवेश के प्रयत्न किए गए। शाहाबाद जिला अंतर्गत ब्रह्मपुर मंदिर और औरंगाबाद के जम्होर में मंदिर हरिजनो के लिए खोल दिए गए। कई स्थानों पर कट्टरपंथी के विरोध का सामना करना पड़ा। आरा में 25 सितम्बर 1932 को एक अवकाश प्राप्त पेशकार श्री रामेश्वर प्रसाद के

मंदिर के सामने सभा हुआ एवं सत्यनारायण पूजा के प्रसाद वितरण के उपरांत कुछ प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इसमें गाँधीजी की जय एवं भारत माता की जय के नारे लगे। प्रांत में धीरे-धीरे परंपरागत विचारवाले लोग के विरोध के बावजूद अस्पृश्यता निवारण के पक्ष में वातावरण तैयार हो रहा था ²¹।

बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन के संचालन हेतु एक प्रांतीय संस्था का गठन किया गया। 6 नवम्बर 1932 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक सम्मेलन सूरजपुरा के राजा राधिकारमण प्रसाद के अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। बिहार के प्रख्यात वैद्व पंडित ब्रज बिहारी चौबे सम्मेलन के स्वागतकारिणी के अध्यक्ष थे। श्री चौबे के अनुसार—“यह प्रथा हिन्दू समाज को खोखला कर रही है एवं हिन्दूओं को तथाकथित अछूत भाइयों के साथ भाईचारा एवं प्रेम व्यवहार की अपील की। उनके सामाजिक शैक्षणिक उत्थान के लिए हर तरह के सुविधाओं के आयोजन करने पर बल दिया। इस सम्मेलन में पाँच प्रस्ताव स्वीकृत किए गए —

- 1 हिन्दू समाज में छुआछूत व्याप्त हो गई है, यह एक सामाजिक अभिशाप है इसे दूर करें।
- 2 स्वर्ण हिन्दू अपने कुओं, मंदिर और तालाब पर से अछूतों के उपयोग करने पर सभी प्रतिबंध हटा दें।
- 3 दलित लोगों के खान-पान तथा रहन सहन में आवश्यक सुधार करके आंदोलन को तीव्रता प्रदान करें।
- 4 स्थानीय स्वायत्त संस्थाएँ दलितों के लिए छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करे जिससे सामाजिक कल्याण का कार्य आगे बढ़े।
- 5 अस्पृश्यता निवारक लीग की एक प्रांतीय अधिषद् बनाई जाए।

बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना 6 नवम्बर 1932 में की गई जिसके उपसभापति पंडित ब्रजबिहारी चौबे, राधिका रमण प्रसाद, राय वृजराज कृष्ण और विजय सिंह बनाए गए। बिहार के 14 जिलों में जिला समिति का गठन किया गया जिसमें पटना, गया, आरा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, चम्पारण, दरभंगा, सन्थालपरगना, सारण, पूर्णियाँ, राँची, हजारीबाग और पुरुलिया शामिल थे। अस्पृश्यता के विरुद्ध विशेष प्रचार मुजफ्फरपुर जिला समिति द्वारा सोनपुर मेला, रामनौमी मेला एवं सुस्ता मेला में किया गया। आरा समिति ने ब्रह्मपुर मेला में भाषण एवं इश्तेहार का आयोजन किया। हरिजन दिवस प्रांत भर में मनाएँ गये। इस आयोजन में सर्वर्ण हिन्दू और दलित कई स्थलों पर एक दूसरे के साथ भाई-भाई के रूप में मिले। हरिजन सेवक सघ का हिन्दी संस्करण प्रकाशित किया गया एवं “शास्त्रों की व्यवस्था” शीर्षक पुस्तिका की 10000 प्रतियाँ वितरित की गई। 236 मंदिर दलितों के लिए खोल दिए गए। 257 संयुक्त धार्मिक कीर्तन, कथा, भजन एवं प्रार्थना आयोजित किए गए। पतितपावन भगवान के नाम से भागलपुर के कहलगाँव में एक नया मंदिर खोला गया। शिक्षा के विकास के लिए छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई। प्रांत में 5 कन्या पाठशालाएँ एवं 113 दिन एवं रात्री पाठशालाएँ खोली गई। इसके अलावा जिला समिति मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान करती थी। दलित को स्थानीय संस्थाओं में निशुल्क शिक्षा दिया जाता था। आर्थिक बचत, मितव्ययता एवं महाजनो के शोषण से बचाने के लिए बैंक की स्थापना की गई। नगरपालिका वर्क्स यूनिशन का गठन किया गया। उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थ के आपूर्ति के लिए दूकान भी खोली गई। खादी भण्डार मधुबनी में दलित की नियुक्ति की गई। सारण कमेंटि ने कुछ दलित युवकों को बढई का काम शुरू करने के लिए 15 रुपये का अनुदान दिया गया। सर्वर्ण हिन्दूओं द्वारा हरिजन मुहल्ले में 292 बार जाकर सेवा-कार्य किया और अनेक स्थानों पर साबुन, सोडा एवं तेल बाँटे गये। दलितों को नशाबंदी करने हेतु अपील की गई जिसमें दलितों ने कई स्थानों पर ताड़ी-शराब

आदि न पीने एवं मृतक जानवरों के मांस न खाने की संकल्प लिया। 646 कुएँ दलितों को पानी लेने के लिए खोल दिए गये। मुंगेर जिला में स्थानीय संस्थाओं ने दलितों के लिए 14 कुएँ बनवाये एवं एक नलकूप लगाया गया। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा एवं आरा नगरपालिका के लिए सरकार द्वारा एक दलित को नगरपालिका का सदस्य मनोनीत किया गया। पुरुलिया में दलितों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता आ आयोजन किया गया जिसमें शील्ड एवं मेडल दिए जाते थे। प्रतिसंध्या सामाजिक-धार्मिक सभाएँ होती थी जिसमें कीर्तन-भजन के साथ रामायण एवं महाभारत का पाठ किया जाता था।

15 जनवरी 1934 को बिहार के उत्तरी भाग में भयानक भूकम्प आया। इस प्राकृतिक आपदा से लगभग बीस हजार लोग हताहत हुए। गाँधीजी ने अपनी दक्षिण भारत के हरिजन यात्रा स्थगित करके 11 मार्च को पटना पहुँचे और पटना के सेन्ट्रल रिलीफ कमिटी के दफ्तर में ठहरे। 14 मार्च को राजेन्द्र बाबू के साथ मोतिहारी के लिए रवाना हुए। अगले दिन गाँधीजी अपनी मंडली सहित देहातो के लिए रवाना हुए, उनकी मंडली में राजेन्द्र बाबू, मथुरा बाबू, श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती किशुन देवी, श्री प्यारेलाल, श्री पृथ्वीराज एवं श्री देवराज शामिल थे। ये रिलीफ कमिटी के लिए पैसा एकत्र करते एवं जरूरतमंदों के बीच बाँट देते। गाँधीजी इस दैवी आपदा में अस्पृश्यता उन्मूलन से जोड़ दिया। छपरा में 27 मार्च को 30 हजार लोगों के सम्बोधन में उन्होंने कहा—“आज हम पर एक भयानक विपत्ति आई है। इससे हम सभी हिन्दू-मुसलमान, ईसाई या अन्य लोग तथाकथित कुलीन या अकुलीन एक समान पीड़ित हुए हैं। यदि यह भयानक विपत्ति भी हमें कुल और वर्ण से मुक्त नहीं करती और आदमी और आदमी के बीच के सभी मानवकृत भेदों को मिटा देने की प्रेरणा नहीं देती तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे समान कोई अभाग नहीं है।” इसप्रकार गाँधीजी अस्पृश्यता को चुनौती देकर जागरूक करने का प्रयास किया ²²।

11 से 27 मार्च के बीच दानापुर अनाथालय में सम्बोधन में छात्रों को इस संकट काल में आगे आकर सहायता कार्यों में हाथ बँटाने की अपील की। 28 मार्च को मुजफ्फरपुर गए जहाँ एक डोम ने प्रतिवेदन देकर कुँए से पानी नहीं लेने देने की जानकारी दी। इसपर गाँधीजी ने कहा कि 15 जनवरी से सबक हमने नहीं सीखी। यहाँ से वे जूरनछपरा गए जहाँ उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए प्रार्थना की तथा छुआछूत निवारण पर बल दिया और राशन अधिशेष के लिए चंदा भी एकत्र किया। 29 मार्च को सीतामढ़ी गए वहाँ से 31 मार्च को मधुबनी, भागलपुर, सहरसा, बीहपुर होते हुए 2 अप्रैल को भागलपुर पहुँचे। 3 अप्रैल को गाँधीजी मुंगेर गए और वहाँ से पटना आने के दौरान मोकामा, पण्डारक, बाढ़ एवं बख्तियारपुर गए जहाँ रास्ते में कुछ सनातनीयों ने काले झण्डे दिखाए। इस दौरान रिलीफ कमिटी ने तीन महीनों में लगभग 25000 कुएँ खुदवाए गए और गाँववाले को समझाबुझाकर दलितों को भी उसमें से पानी लेने को राजी करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक असम की यात्रा पर रहें और पुनः 24 अप्रैल से दूसरी हरिजन यात्रा बिहार में प्रारंभ की। इस बार 25 अप्रैल को वे कुलहरिया पहुँचे और वहाँ से बाबू राधामोहन सिंह के आमंत्रण पर जम्हरिया गए। यहाँ करीब दस हजार लोगों को सम्बोधन किया। सभा में हरिजन बालकों ने स्वागत गान गाया एवं माला पहनायी। आरा जिला अस्पृश्यता निवारक संघ के अध्यक्ष राजा राधिकारमण प्रसाद सिन्हा, बाबू शत्रुंजय प्रसाद सिंह तथा बाबू भगत प्रसाद ने उन्हें चंदा प्रदान किया। इसी दिन बक्सर गए जहाँ सनातनियों ने रास्तों में सभाओं में कुछ गडबडी फैलाने का प्रयास किया एवं कालं झण्डे दिखाए। 26 अप्रैल को जसीडीह पहुँचे वहाँ भी सनातनियों ने बाधा डालना चाहा। उनके गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया, वे गाड़ी से उतरकर सनातनियों के बीच से होकर लगभग एक

मील पैदल चले। देवघर में भी विरोध प्रदर्शन हुए। गाँधीजी ने प्रदर्शन के तरीके के लिए खेद प्रकट किया। अप्रैल के अंत में चार दिन तक राँची में रहने के उपरांत उड़ीसा गये इसप्रकार अपनी अधूरी हरिजन यात्रा बिहार से समाप्त की²³।

महात्मा गाँधी ने जातीय पूर्वाग्रह से उत्पन्न अस्पृश्यता का आजीवन विरोध करते रहे, उन्होंने हिन्दू मुस्लिम भाईचारे के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। गाँधी से प्रेरित भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता दूर करने हेतु कानून बनाए, धर्म के मामले में राज्य की निरपेक्षता कायम की। संविधान ने नागरिकों को समान राजनैतिक अधिकार प्रदान किए और अनुच्छेद-17 द्वारा अस्पृश्यता को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। 1955 में संसद ने अस्पृश्यता अपराध एक्ट बनाकर ऐसे अपराधों के लिए दण्ड की व्यवस्था की। 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट पारित किया गया।

संदर्भ सूची

1. डॉ. के. के. दत्त: बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, भाग-2, पेज संख्या-186
तेन्दुलकर में उद्धृत, खण्ड-3, पेज-217
2. शेखर बंद्योपाध्याय: पलासी से विभाजन तक और उसके बाद, पेज संख्या-350
गाँधी पॉलिटिकल फिलॉसॉफी: अ क्रिटिकल इग्जामिनेशन 1989, पारेख भीखू नॉट्रेडम इंडियाना, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉट्रेडम प्रेस
3. सत्य के प्रयोग: आत्मकथा
4. सत्य के प्रयोग आत्मकथा: प्रिटोरिया जाते हुए, पेज-78
5. वही, कुली लोकेशन या भंगी बस्ती, पेज संख्या-188
6. शेखर बंद्योपाध्याय: पलासी से विभाजन तक और उसके बाद, पेज संख्या-350
बेली सूसर्न: कास्ट सोसाइसी एण्ड पालिटिक्स इन इंडिया फ्रॉम एटिन्थ सेंचूरी, 1999 पेज-251
7. सत्य के प्रयोग: आत्मकथा, कसौटी पर चढ़े, पेज संख्या-258
8. झा एण्ड श्रीमाली: प्राचीन भारत का इतिहास
9. शेखर बंद्योपाध्याय: पलासी से विभाजन तक और उसके बाद, पेज संख्या-339
10. वही, पेज संख्या-339
11. वही, पेज संख्या-340
12. झा एण्ड श्रीमाली: प्राचीन भारत का इतिहास
13. शेखर बंद्योपाध्याय: पलासी से विभाजन तक और उसके बाद, पेज संख्या-340
14. वही, पेज-343
15. वही, पेज-343
16. वही, पेज-345
17. वही, पेज-351
18. विपिन चन्द्र: भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, पेज-275
19. वही, पेज-276
20. वही, पेज-278
21. डॉ. के. के. दत्त: बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, भाग-2, पेज संख्या-188, 189, 199, एवं 192
22. वही, पेज संख्या-202, 205, 206,
23. वही, पेज संख्या-208, 211, 214 एवं 215